RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

कोरकू जमात की सांस्कृतिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]डॉ. संकेत सुरेशराव काले; [2]रोहित रामसिंह येवतीकर

[1]शोध निर्देशक श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझनूं, राजस्थान
[2]शोधार्थी श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझनूं, राजस्थान

प्रस्तावना

आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था का स्वरुप भिन्न है. क्योंकि उस समाज में लोगों की जरुरतें और उन्हें पूरा करने की प्रणाली भी अलग देखने मिलती है आर्थिक समस्याएं हल करने के स्वरुप पर संबंधित समाज की अर्थव्यवस्था का स्वरुप निर्भर रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में महाराष्ट्र में आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उन्होंने लाभ ली गयी सरकारी योजनाओं का अभ्यास किया गया है। उन्हें किस प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पडता है इसे रखने का प्रयास किया गया है। आदिवासी महिलाएं खेती के काम खत्म होने के बाद जंगल में तेंदुपत्ता एकत्रित करना, मोहा के फूल तथा डिंक संकलन करना इसी तरह लकडी एकत्रित करना साथ में रोजगार गारंटी योजना के काम करती है। आदिवासी जनजाति में उत्तरदाता की परिवार की वार्षिक आय कम है लेकिन आदिवासी महिलाओं का परिवार में आर्थिक सहयोग मिलता है। बावजूद इसके उत्तरदाता परिवारों में कर्ज बाजारीपन अधिक मात्रा में दिखाई देता है। आदिवासी विकास के बारे में प्रशासन और आम आदिवासी लोगों के दृष्टिकोण का अंतर यह रहना चाहिए नेहरू के पंचशील की भूमिका के विपरित आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के विकास के लिए सरकार द्वारा बार–बार अनेक योजनाएं प्रसारित की गयी है. आमतौर पर 50 फीसदी आदिवासी लोगों को केवल शिक्षा और विद्यालय छोडने के कारण इन योजनाओं की जानकारी नहीं है और जिन्हें जानकारी है उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए विवरण तथा दस्तावेजी पूर्ति करने में दिक्कत आती है। सैकडों साल के भौगोलिक अलगाव और बाहर के लोगों द्वारा स्थायी शोषण करने के कारण आदिवासियों को बाहरी दूनिया की जानकारी नहीं रहती है. इससे बाहरी दुनिया के बारे में संदेह की भावना रहती है. सरकारी योजनाओं के लोगों को लाभ प्राप्त करने का अनुभव नहीं रहता है। इस कारण आदिवासी विकास प्रशासन के बारे में लोगों को पूरा विश्वास नही रहता है. जहां विकास के आधारभूत सुविधाएं पैदा हुई है। उन सुविधाओं का उपयोग कर अपना जीवनस्तर उपर उठाने की क्षमता आदिवासियों में नहीं है. इस क्षमता के अभाव के कारण आदिवासी समाज पिछडा है।

आजादी के बाद गांव का विकास करने के लिए सामूहिक विकास योजना 1952 में बनाई गयी. इससे आगे ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए पंचायत राज योजना लागू की गयी लेकिन इससे भी आदिवासी समाज तथा ग्रामीण विकास से कोसो से दूर रहे इसमें महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी. इस पर सरकार ने 73 वीं संविधान संशोधन करते हुए पंचायत राज व्यवस्था में पिछड़ों को विशेष आरक्षण और महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया गया. इसी तरह पंचायत राज व्यवस्था में पिछड़ों को और महिलाओं को राजनीति और समाज में स्थान देकर उनके सक्षमीकरण पर जोर दिया दिखाई दे रहा है। इसके कारण आदिवासी महिलाओं में भी राजनीतिक नेतृत्व सामने आ रहा है इसमें राज्य व केन्द्र सरकार के आदिवासी व समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का प्रभाव आदिवासी समाज में राजनीतिक नेतृत्व पर होता दिखाई दे रहा है लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं पर अमल ईमानदारी से नहीं होने के कारण तथा कर्मचारियों की काम में लापरवाही से जरुरतमंद आदिवासी महिलाओं को योजनाओं का जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आदिवासी महिलाओं का परिवार परंपरागत व्यवसाय खेती है। लेकिन जनजाति में अल्प भूधारक एवं अनुपजाऊ खेती की मात्रा अधिक रहने के कारण उन्हें खेत मजदूरी तथा जंगल की संपत्ति पर परिवार का गुजारा करना पडता है. महाराष्ट्र में जमीन मालिकाना का औसत घट रहा है।

इस प्रकरण में आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक स्थिति तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेते समय आनेवाली समस्याओं का अध्ययन करते समय उत्तरदाता परिवारों के पास खेती है क्या, यदि है तो कितनी है, वह किस स्वरुप की है? उनके पास सिंचाई के साधन कौन से है?, व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय कितनी है? इसी प्रकार खेती का मौसम खत्म होने के बाद उन्हें कौन से काम करने पडते है? मजदूरी के लिए स्थलांतर करना पडता है क्या? आदिवासी महिलाओं का बचत समूहों में सहभाग है क्या? उन्हें बचत समूहों का कौन सा लाभ हुआ है? होने पर कर्ज का स्रोत क्या है? इस तरह के अनेक सवालों के माध्यम से आदिवासी विकास के लिए जो

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सरकारी योजनाएं है, इस बारे में उत्तरदाताओं में समझ है क्या? या सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें किस तरह प्राप्त होती है? वह इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन सी परेशानीया आती है? इसके मद्देनजर इस प्रकरण का विश्लेषण किया गया है। स्थायी सम्पत्ति मनुष्य बुद्धिमान तथा भविष्य की स्थिति जानने वाला समाज का महत्वपूर्ण घटक है जिस प्रकार जंगल में छोटी सी चिटी अपनी बिल में अन्न–धान्य का कण एकत्रित कर रखती है उसी प्रकार भविष्य की चिंता करने वाला इन्सान भी सम्पत्ति के संचय को प्राथमिकता देता है। स्थायी सम्पत्ति का स्वरूप अलग–अलग तरह का रहता है, प्रमुख रूप से स्थायी सम्पत्ति में रहने का घर (गांव में), जानवरों का तबेला, शहर में स्वयं का घर, शहर में प्लॉट, गहने और किसान विकास पत्र/सरकारी नगद जैसी बातों का समावेश किया जा सकता है. आदिवासियों की परिस्थिती का अवलोकन करने पर आदिवासियों की नजर में उक्त बातें वे सम्पत्ति मानते है। स्थायी सम्पत्ति से आय भी मिलती है. उत्पन्न स्तर में बढोत्तरी होने के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार में मदद मिलती है. हालही में तेजीसे बदलने वाली आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम का असर स्थायी सम्पत्ति पर दिखाई देता है। स्थायी सम्पत्ति आर्थिक स्थिति में सुधार होने का लक्षण मानी जाती है, इसीलिए स्थायी सम्पत्ति महत्वपूर्ण आर्थिक घटक है, जिसके पास आदिवासी जनजाति में स्थायी सम्पत्ति नहीं रहती है। ऐसे में वारली, कातकरी, ढोर कोली तथा ठाकुर जनजाति के कुछ मजदूरी तथा अनउपजाऊ खेती करने वाले दिखाई देते है. उक्त सम्पत्ति रहने वाले आदिवासी निजी कम्पनियों में कामगार के रूप में काम करने वाले, अर्धशासकीय व सरकारी नौकरी करने वाले आदिवासियों ने स्थायी सम्पत्ति धारण की है, लेकिन इसकी मात्रा अल्प है। स्थायी सम्पत्ति का अध्ययन करते समय स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रमुख रूप से मजदूरी करने वाले आदिवासी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचते दिखाई देते है इससे वे वर्तमान में ही जीते दिखाई देते है। इसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे, जीवनस्तर बेहतरीन हो और समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होने जैसे स्वरूप का आशावाद इन आदिवासियों के मन में नहीं दिखाई देता है. आम तौर पर चौथी से सातवीं तक शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासियों के मन में भी इस तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रहने के कारण वे वर्तमान में ही जीने को धन्यता मानते है. अपने पास किसी भी प्रकार की स्थायी सम्पत्ति नहीं रहने का दुःख भी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है, इससे वे स्थायी सम्पत्ति जमा करने की बजाए आजीविका चलाने के बारे में ही विचार करते हैं।

भारतीय समाज को विघटित करने में सांस्कृतिक कारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पुराने और नये सामाजिक मूल्यों एवं अभिवृत्तियों के बीच संघर्ष पाया जाता है। ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होता है जो पारिवारिक और सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में लोगों का पुरानी मान्यताओं, विश्वासों एवं परम्पराओं के प्रति कोई झुकाव नहीं रहा है। अब नैतिकता सम्बन्धी धारणाएँ भी काफी कुछ बदल गयी हैं। आज व्यक्तिवादी एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास भी तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि अब कई व्यक्ति परिवार को भी स्वार्थ पर आधारित इकाई समझने लगे हैं। अब भ्रष्ट साधनों से धन कमाना भी बहुत से लोग बुरा नहीं समझते, अपने पद का दुरूपयोग करना और सार्वजनिक सम्पत्ति का अपने स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयोग करना बहुत से लोग उचित समझने लगे हैं।

सांस्कृतिक पिछड़न (Cultural Lag) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के परिणामस्वरूप संस्कृति का भौतिक पक्ष काफी आगे बढ़ गया, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रियाएँ तीव्र हुई, आवागमन एवं संचार साधनों का तेजी से विकास हुआ। जिस गति से इन सबका विकास एवं भौतिक संस्कृति की प्रगति हुई, उसी गति से अभौतिक संस्कृति में आवश्यक बदलाव नहीं आया अर्थात् सामाजिक मूल्य, प्रथाएँ, परम्पराएँ, विश्वास, मान्यताएँ, व्यवहार के तरीके आदि नहीं बदले। परिणामस्वरूप भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गयी और अभौतिक संस्कृति पिछड़ गयी। इसी को सांस्कृतिक पिछड़न कहते हैं। इस स्थिति ने पुरानी और नयी पीढ़ी के बीच वैचारिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी। नयी पीढ़ी पुराने सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, व्यवहार के तरीकों आदि को नयी बदली हुई परिस्थितियों में अनुपयोगी मानने लगी। पीढ़ियों के इस संघर्ष व सांस्कृतिक पिछड़न के परिणामस्वरूप उत्पन्न असन्तुलन की स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने हेतु समाज–सुधार एवं समाज कल्याण के व्यापक कार्यक्रम चले। इन सबके फलस्वरूप भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था।

जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित सम्बन्धों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से सम्बन्धित होती हैं और अपने–अपने स्थान पर अपेक्षातया स्थिर रहती हैं। इन सभी के संयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना को स्पष्टतः समझने के लिए हम यहाँ इसकी परिभाषा एवं विभिन्न विद्वानों द्वारा उसके बारे में प्रकट किए गए विचारों का उल्लेख करेंगे।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था विश्व की प्रभुत्व सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय सामाजिक जीवन विशिष्ट संस्कृति, विविधता एवं एकता, अनुपमता एवं प्राचीनता के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश भी अनेकताओं और बहुरूपताओं से भरा–पूरा है, परन्तु फिर भी भारतीय जीवन व संस्कृति की अनेक अभिव्यक्तियों के

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पीछे आत्मा की एकता विद्यमान है। इस एकता व विविधता ने ही भारतीय समाज को निरंतरता प्रदान की है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्र भारत तक भारतीय कला, धर्म, सामाजिक व्यवस्था में सदैव ही सात्विकरण और समिश्रण की प्रक्रिया के कारण सत्तता बनी रही है।

भारतीय समाज व संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट जीवन विधि रही है, परन्तु समय–समय पर बाहर से आने वाली संस्कृतियों के सम्पर्क में आने के कारण इसमें परिवर्तन व संशोधन होते रहे हैं। समन्वय व सहिष्णुता की प्रकृति के कारण धर्म, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य व समाज व्यवस्था में एक तरफा जहाँ अनेक विविधताएं पनपीं वही दूसरी तरफ भारतीय समाज समृद्ध भी हुआ तथा अपने निजी विचारों एवं सिद्धांतों के कारण भारतीय जीवन विधियाँ बनी रहीं। भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है। इसका इतिहास करीबन 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ ऋषि–मुनियों, विचारकों एवं चिन्तकों ने अपने अनुभव और चिन्तन के आधार पर एक ऐसी मानव संस्कृति के विकास में योग दिया जिसने सदियों तक मानव का मार्गदर्शन किया तथा भारतीय विचारकों ने ऐसे जीवन मूल्यों और आदर्शों को निर्मित किया जो व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हुए। वर्तमान मे समाज परिवर्तन के प्रवाह में बदलता रहा तथा इसकी संस्थाओं, परम्पराओं, अर्थव्यवस्थाओं, राजनैतिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था, पारिवारिक एवं जातिव्यवस्था, कला तथा संस्कृति में बदलाव आता रहा। उदाहरण के लिए एक तरफ सामान्य बालक हैं तो दूसरे पिछड़े बालक हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों एवं भाषाओं से सम्बंधित समूह सारे देश मे फैले हुऐ हैं। यह पिछड़े समूह भी अनेक सम्प्रदायों, जातियों, गोत्रों व भाषाओं मे विभक्त है। इन पिछड़े के लोगों को अच्छी शिक्षा, रोजगार व अच्छा जीवन स्तर प्राप्त नहीं है इसलिये ये न्याय से वंचित हैं। इस प्रकार के निर्धन व धनी वर्ग के बीच असमानता स्वयं भारतीय समाज की देन है, जिसके कारण समाज में समय–समय पर तनाव व संघर्ष पैदा होता रहता है तथा परस्पर मानसिक तनाव व कुंठाएँ बैठती रही हैं। इन कारणों से भारत की आंतरिक एकता, सम्बंध चेतना व भारतीयता की भावना को गहरा आघात लगा। यह स्थिति भारतीय समाज की सरंचना के स्वरूप और वास्तविकता के बीच भेद के कारण उत्पन हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पूजाश्री चैटर्जी (2014), ''सोशल एण्ड इकॉनॉमिक स्टेटस् आफ ट्रायबल वूमन इन इंडिया – दी चैलेजेस एण्ड दी रोड अहडे'', इंटरनेशनल जरनल आफ इंटरडिसिप्लीनरी एण्ड मल्टीडिसिप्लीनरी स्टडीज (आयजेआयएमएस) वोल्यूम 02, पेज संख्या 60, आयएसएसएन–2348–0343.
2. एस. पोन्नारासु एण्ड एस. मोदेवन (2017), ''ए स्टडी ऑन सोशियो–इकॉनॉमिक एण्ड हेल्थ कंडीशन्स आफ दी ट्रायबल पीपल्स आफ दी निलगिरी डिस्ट्रीक्ट –तमिलनाडू'', इम्पेरियल जरनल आफ इंटरडिसिप्लीनरी रिसर्च (आयजेआयआर), वोल्यूम 03, इश्यू –1, पेज संख्या 30, आयएसएसएन– 2454–1362.
3. कल्पना वी. जवले (2015), ''एनालिसीस आफ दी प्रॉब्लेम आफ मालन्यूट्रीशन इन मेलघाट एरिया आफ महाराष्ट्र – ए सोशियो लीगल स्टडी'', इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लीनरी रिसर्च जरनल, वोल्यूम 05, इश्यू 1, पेज संख्या 305, आयएसएसएन–2249–9598.
4. श्रबंती मैती, व्हीक्टोरिया हैवबिजम एण्ड अलोक सेन (2014), ''सोशियो इकॉनॉमिक स्टेटस् आफ कुकी ट्रायबल वूमन : ए केस स्टडी चुरचंडपुर डिस्ट्रीक्ट मनीपुर'', अमेरिकन–यूरोसियन जरनल आफ साइन्टीफिक रिसर्च, वोल्यूम 09, इश्यू –05, आयएसएसएन–1818–675.
5. तोसिब आलम, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद आसिफ (2009), ''सोशियो–इकॉनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्रायबल वुमन एन इंडियन पर्सपेक्टीव'', इन्टरनेशनल जरनल ऑफ रूरल स्टडीज (आयजेआरएस) (2009), वोल्यूम 10, पृष्ठ संख्या 11, आयएसएसएन–1023–2001.
6. ए. अँगेल ॲनिला (2012), ''ए स्टडी आन सोशियो–इकॉनॉमिक कंडीशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बरस् इन टीरुनेलवेली डिस्ट्रीक्ट, तमिलनाडू'', झेनिथ इंटरनेशनल जरनल आफ बिजनेस इकॉनॉमिक्स एण्ड मैनेजमेंट रिसर्च, वोल्यूम 2, नं. 2, पेज संख्या 216, आयएसएसएन–2249–8826.

RRIJM 2015, All Rights Reserved